R.N.I. No. RAJHIN/2019/77793

postal reg.no. RJ/RJ/207/2022/2024

मरुधरा टुडे

पाक्षिक

विज्ञापन एवं वार्षिक सदस्यता हेतु कार्यकारी सम्पादक - सहर
मो. 8107416712

वर्ष 06 अंक 8 | कुल पृष्ठ 4 | अजमेर, गुरुवार, 1 अगस्त, 2024 | Email.Id: marudharatoday.info@gmail.com | मूल्य : 3 /- रुपये

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें, एनएफएसए के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर, 1 सितंबर 2024 से लागू होंगी

वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का प्रत्युत्तर- वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी भर्ती, भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी होंगे विकास प्राधिकरण - खुशहाली लाने वाला और सर्वजनहिताय की सोच वाला बजट - बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर की योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर दिया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गरीब, पिछड़ा एवं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए 24x7 कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजनहिताय की सोच वाला, समाज के सभी वर्गों-युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे।

1953 से 2014 के बीच 50 से अधिक बार बर्खास्त हुई राज्य सरकारें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र में काला दिवस था। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाला, न्यायालय के अधिकारों पर कुठाराघात किया और मीडिया पर सेंसरशिप लागू की। साथ ही 1953 से 2014 के बीच 50 बार से अधिक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनहित का काम करती है, नाम बदलने की राजनीति नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अटल सेवा केन्द्र का नाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र करने एवं अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना करने का कार्य किया गया।

पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की घोषणाओं की क्रियान्विति

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।

45 हजार से अधिक भर्तियां, 20 हजार युवाओं को मिली नौकरी

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू नहीं किया गया। साथ ही, यमुना जल समझौते के लिए एक मांग पत्र भी नहीं लिखा गया। वहीं हमने प्रदेशहित में इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।

1 हजार करोड़ रुपये से बनेंगे अटल प्रगति पथ

इस दौरान श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 के अंतर्गत प्रदेश की ढाई हजार से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 1 हजार 100 करोड़ रुपये के अधिक की राशि के कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 ई-बस उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की।

भरतपुर एवं बीकानेर में बनेंगे विकास प्राधिकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर वहां विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सम्पादित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना बनाई जाएगी। उन्होंने 10 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों एवं निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए 100 कलस्टरों में चरणबद्ध रूप से फेकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य एवं दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़ (झुंझुनूं), सांगोद (कोटा) में सीवरेज लाईन के कार्य, चेचट एवं खैराबाद कस्बों में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई एवं पुनर्निर्माण कार्यों की घोषणा भी की।

पेयजल संबंधी 9 कार्यों के लिए 540 करोड़ रुपये की घोषणा

शर्मा ने प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-3)-जयपुर (फेज-2) के लिए कॉमन इंटेक वैल मय ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण सहित पेयजल संबंधी 9 कार्य 540 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाटर टेस्टिंग लैब्स को राष्ट्रीय स्तर का बनाकर एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने हेतु 15 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, वाटर टेस्टिंग सेंपल्स को जीओ टेगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा।

एससीआईएल और गेल से एमओयू कर 4100 मेगावाट क्षमता का होगा सृजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एससीआईएल और गेल से एमओयू करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। उन्होंने किसानों के खेत पर कुसुम परियोजना/हैम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश में हैम मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से चरणबद्ध रूप से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने एवं विभिन्न क्षमता के 4 जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा भी की।

खुशियारा एवं पण्डेर में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क

शर्मा ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किए जाने, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दस्ताकारों को दिये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने, खुशियारा (बारां) एवं पण्डेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क स्थापित किये जाने की घोषणा की।

चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी होगी भर्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने भर्तियों में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराये जाने एवं विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन किया जाकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी।

उन्होंने सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालीफिकेशन हेतु सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 नवीन महाविद्यालयों, 3 नवीन कन्या महाविद्यालयों, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक एवं एक महिला पॉलिटेक्निक सहित शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से कई महत्वूपर्ण घोषणाएं भी की।

एम्स की तर्ज पर प्रदेश में बनेगा आरआईएमएस

शर्मा ने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा भी की।

शेष पृष्ठ 2पर..

संपादकीय

फिर आतंकी हमलें, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाये

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खूनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खूनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी। लगातार जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं चिन्ता का कारण बन रही है। डोडा जिले में एक आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के चार जवानों और जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी का बलिदान अब यही दर्शा रहा है कि शांति एवं अमन की ओर लौटा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर आतंकवादी आघातकारी घटनाओं की भेंट चढ़ रहा है, इन घटनाओं का माकुल जबाव नहीं दिया गया तो यह घाटी एक बार फिर खूनी घाटी बन जायेगी। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कठुआ में एक सैन्य अफसर सहित पांच जवान आतंकियों का निशाना बन गए थे। इसके पहले भी जम्मू संभाग में ही सेना के कई जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। ये बहुत चिंतित करने वाले त्रासद एवं घिनौने घटनाक्रम हैं कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल की कुछ घटनाओं से तो यह भी लगता है कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। एक ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, तब आतंकियों का सक्रिय होना और सफलतापूर्वक अपने मनसूबों को कामयाब करना गंभीर चिंता का विषय है। ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खूनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खूनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी। हमें इस काम में पूरी शक्ति और कौशल लगाना होगा। आदमखोरों की मांद तक जाना होगा। अन्यथा हमारी खोजी एजेंसियों एवं सेना की काबिलीयत पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा कि कोई दो-चार व्यक्ति कभी भी पूरे प्रांत की शांति और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, हमारी संवेदनाओं को झकझोर सकते हैं। संवेदनाओं एवं भावनाओं को झकझोर भी रहे हैं, जब आतंकवादी हमलों में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे घर की ड्योढ़ी पर आते हैं तब कारुणिक माहौल को देखकर दिल दहल उठता है क्योंकि देश के लिए अपना सर्वोच्च लुटा देने वाला जवान किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता होता है। हर आंख में आंसू होते हैं। किसी की गोद, किसी की मांग सूनी हो जाती है। देशवासी सोचने को विवश हैं कि वे शोक संतप्त परिवार के साथ करुणा और पीड़ा को कैसे बांटें।

लायंस क्लब भीलवाड़ा रूबी द्वारा वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट का विमोचन

भीलवाडा। लायंस क्लब भीलवाड़ा रूबी द्वारा वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट का विमोचन किया गया। सचिव लायन सुधा जैन ने बताया की पीडीजी, पीएमसीसी लायन अरविंद शर्मा, पीडीजी. पीएमसीएस लायन दिलीप तोषनीवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन श्यामसुंदर मंत्री एवं रीजन चेययपर्सन लायन राकेश पगारिया के सानिध्य मे अध्यक्ष लायन मधु काबरा के द्वारा वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट का विमोचन किया गया। इस किट में कॉटन, बैंडेज, बेंडेड, स्पिरिट, मल्हम जरूरत पड़ने पर हार्ट अटैक की गोलियां भी रखी है। यह किट दोपहिया व चार पहिया वाहन के लिए सभी को वितरित किए जाएगें ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें लगाकर हम अस्पताल तक पहुंच या पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में माइक्रो कैबिनेट चेयरपर्सन लायन मंजू पोखरना, लायंस क्लब भीलवाड़ा स्टार के अध्यक्ष अंकुर जैन, लायन ओ पी काबरा, विनोद जैन, रूबी क्लब कोषाध्यक्ष ममता शर्मा, निखिल काबरा सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

अंगदान के प्रति जागरूकता के लिए चलाएं अभियान, इससे जुड़ी सेवाओं का हो विस्तार - राज्यपाल श्री मिश्र इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अंगदान एवं प्रत्यारोपण जागरुकता संवाद और सम्मान समारोह आयोजित

जयपुर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जांन गंवा रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इसके मद्देनजर अंगदान के प्रति जागरूकता का सघन अभियान चलाना जरूरी है।

राज्यपाल श्री मिश्र ने सोमवार को रवींद्र रंगमंच में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और स्टे ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंगदान एवं प्रत्यारोपण जागरूकता संवाद तथा सम्मान समारोह में कहा कि अंगदान मानवता के लिए समर्पण से जुड़ा कार्य है। उन्होंने अंगदान कर दूसरों को नया जीवन देने वाली महान आत्माओं को नमन भी किया ।

राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश महर्षि दधीचि जैसे ऋषियों का देश है, जिन्होंने असुरों से रक्षा के लिए शस्त्र बनाने के लिए अपनी देहदान कर दी। उनकी हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण हुआ जिससे इन्द्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बताया कि भारत में प्रति दस लाख आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं। वहीं प्रति दस लाख की आबादी पर स्पेन में 36, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं।

मिश्र ने कहा कि स्पेन अंगदान और प्रत्यारोपण के मामले में अग्रणी है। यूरोपियन यूनियन ने भी अंगदान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। भारत में भी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन इस दिशा में काम कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस के अंगदान जागरूकता कार्यक्रम से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान में अंगदान की जागरूकता के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए और राज्य में अंगदान से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हो। जहाँ अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरण मौजूद हैं, वे सभी राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के साथ पंजीकृत हों। उन्होंने कहा कि यदि अंगदान में वाणिज्यिक प्रयोग की प्रवृत्ति यदि पाई जाती है तो वह समाज के लिए कलंक है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने %आयुष्मान भारत' योजना के माध्यम से अंगदान और प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित किया है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में निरंतर कार्यरत है और अंगदान को जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसपी मेडिकल कॉलेज ने अंगदान जागरूकता और प्रत्यारोपण में कई सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने आह्वान किया कि मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों को अंगदान की महत्ता बताई जाए जिससे वे अपने पेशेवर जीवन में इस नेक कार्य को प्रोत्साहित कर सकें।

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के प्रदेश चेयरमैन श्री राजेश कृष्ण बिड़ला ने कहा कि सोसायटी आपदा प्रबंधन के साथ सामाजिक सरोकारों के काम कर रही है। अंगदान के प्रति जागरूकता इसमें सबसे महत्वपूर्ण है।

इससे पहले राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कर्मकांडी पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के स्टेट वाइस चेयरमैन श्री विजय खत्री ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने सोसायटी की अब तक की गतिविधियों की जानकारी दी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. धनंजय अग्रवाल ने कहा कि बीकानेर में जल्दी ही अंग प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अंग प्रत्यारोपण महायज्ञ है। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए।

राजस्थान अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के सलाहकार डॉ. धर्मेश कुमार शर्मा ने अंगदान एवं प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता पर प्रस्तुतिकरण दिया।

राज्यपाल ने अंगदान के प्रति जागरूकता से जुड़े पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान अंगदाता स्व. श्री

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें, एनएफएसए के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर, ...

राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विजयदान देथा साहित्य उत्सव

मुख्यमंत्री ने राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्यों के लिए भी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने के लिए विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्यों करवाये जाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि किसानों को फसल, फसली रोग एवं विपणन संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान कर राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना सहित विभिन्न घोषणाएं की।

डीड राइटर्स की संख्या होगी 5 हजार- शर्मा ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर की स्थापना करने, तिजारा (खैरथल) में बॉर्डर होमगार्डस की एक कंपनी तैनात किए जाने, अजमेर/जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किये जाने, डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी कर 5 हजार किये जाने, विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

मुख्यमंत्री ने गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशों को 1 सितंबर, 2024 से लागू करने, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की घोषणा की। उन्होंने पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की।

स्वामी व प्रकाशक महेश चंद रांगेरा दवारा मुद्रक गोपाल सिंह लबाना, गुरुनानक प्रिंटिंग प्रसे, प्लॉट नम्बर 2, पत्रकार कॉलोनी, कोटड़ा, अजमेर से मुद्रित व कार्यालय जी-7सातवीं मंजिल, गुरु अभय रेडिडेन्सी, पंचशील ब्लॉक, अजमेर से प्रकाशित, सम्पादक -महेश चंद रांगेरा व कार्यकारी सम्पादक-सहर। समस्त विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र अजमेर ही रहेगा। मो. 9929590449, 8107416712, Email.Id: marudharatoday.info@gmail.com

राजुवास का सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित विश्वविद्यालय पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के नवीन पाठ्यक्रमों की पहल करे- राज्यपाल

जयपुर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालय पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के नवीन पाठ्यक्रमों की पहल करे। उन्होंने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पशु धन उत्पादों के प्रसंस्करण के साथ विपणन से जुड़े अधिकाधिक कार्य किए जाने का आह्वान किया।

राज्यपाल श्री मिश्र सोमवार को बीकानेर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।राज्यपाल ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि जोत, पानी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पशुधन और पशु उत्पाद पोषण सुरक्षा की दृष्टि से वरदान साबित हो सकते हैं। इसके लिए खाद्य और दुग्ध उद्योग में छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि राजुवास तीन संघटक पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों, एक डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, आठ सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा 101 डिप्लोमा संस्थानों के माध्यम से प्रदेश में पशु चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षण के तहत पशुधन संरक्षण, प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक के बारे में पशुपालकों से जानकारियां साझा करें।श्री मिश्र ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन की हमारी संस्कृति रही है। खेतीबाड़ी, आय अर्जन के साथ पोषण सुरक्षा का भी माध्यम है। श्री मिश्र ने आह्वान किया कि नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशु-सम्पदा रोग निदान और उपचार के साथ साथ उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे।राज्यपाल श्री मिश्र ने पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह की बधाई दी और कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों के बजाय बेटियों ने अधिक बेहतर परिणाम देकर पशुचिकित्सा के क्षेत्र में भी स्वयं को साबित किया है।

ये परिणाम प्रतिस्थापित करते हैं कि जिस समाज में बेटियों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिले हैं, वह तेजी से विकास की राहों पर अग्रसर होता है।राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के पारम्परिक पशु चिकित्सा, पशु चारा संसाधन, जैविक उत्पादन, जैव विविधता संरक्षण, बायो-मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एवं पशु आपदा प्रबंधन, पशुविज्ञान अभियांत्रिकी केन्द्र ,विद्यार्थियों की उपाधियां को डिजीलॉकर पर उपलब्ध करवाने तथा %इनक्यूबेसन सेन्टर' स्थापना को बेहतर पहल बताया। श्री मिश्र ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अन्तर्गत %एक विद्यार्थी-एक पेड़ की संकल्पना में हर विद्यार्थी को भागीदारी का आह्वान किया।

कुलपति प्रो. सतीश गर्ग ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो नज़ीर अहमद गनई ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने में जुट जाएं।

राज्यपाल ने समारोह के दौरान 538 छात्र-छात्राओं को स्नातक, 106 को स्नातकोत्तर एवं 21 को विद्यावाचस्पति की उपाधियां प्रदान की। इसी तरह 29 विद्यार्थियों को उनके उत्कृट शैक्षणिक प्रदर्शन के फलस्वरूप विभिन्न पदक प्रदान किये गए। राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां डीजी लॉकर पर अपलोड की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया। इससे पूर्व राज्यपाल श्री मिश्र ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया तथा संविधान के मूल कर्तव्यों का पठन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने जोधपुर के नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन, शालिहोत्रा भवन, स्वामी विवेकानंद छात्रावास, बीकानेर प्रांगण में भगिनी निवेदिता छात्रावास व शालिहोत्र अति-विशिष्ट अतिथि गृह आदि कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 सहायक आचार्य-गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट- आयोग ने जारी की साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य - गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट विषय की परीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

आयोग सचिव ने बताया कि गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट विषय के 1 पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णत: अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है।

उक्त विषय के प्रश्न-पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षाओं का आयोजन गत 31 मार्च तथा प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन गत 7 जनवरी को किया गया था।

साक्षात्कार हेतु अस्थाई रुप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रुप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति के आगामी 12 अगस्त सायं 6 बजे तक आवश्यक रुप से आयोग कार्यालय में भिजवा दें।

उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जाएगा।

साक्षात्कार की तिथि के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत करवा दिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि तीन माह से घटाकर एक माह की - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि एक माह हो गई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय यह अवधि तीन माह से अधिक थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 1000 रूपये से 1150 रूपये किया गया है। वर्तमान में पेंशनर्स को एक अप्रेल, 2024 से बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 89 लाख पेंशनर्स के खातों में 1037 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। इससे पहले विधायक श्री अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि 01 जनवरी, 2024 को प्रदेश मे विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था श्रेणियों में पात्रता अनुसार केन्द्र प्रवर्तित एव राज्य द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 86,84,100 व्यक्तियों को लाभांवित किया जा रहा है। उन्होंने जिलेवार, वर्षवार व वर्गवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने पिछले तीन वर्ष में वर्गवार एवं जिलेवार पेंशन लाभार्थियों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

अन्य राज्य की महिला राज्य के मूल निवासी पुरुष से विवाह करे तो वह राजस्थान की मूल निवासी -- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नियमानुसार राज्य से बाहर की महिला के, राजस्थान के मूल निवासी पुरूष से विवाह करने के बाद राज्य में ही निवास करने की स्थिति में, महिला को राज्य का मूल निवासी मान लिया जाता है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र 28 अगस्त, 2012 के तहत राज्य से बाहर की महिला के राज्य के मूल निवासी पुरूष के साथ विवाह कर राज्य में ही रहने पर उसे 10 वर्ष के निवास की शर्त के बिना ही राज्य का मूल निवासी माना जाता है। इससे पहले विधायक श्री मनोज कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र 21 अक्टूबर, 2002 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्वंय के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण पत्र जारी नही किया जा सकता है,

होम गार्ड्स को महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रावधान नहीं -गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री

जयपुर। गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है, जिन्हें अन्य विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर रोस्टर प्रणाली द्वारा नियोजित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि स्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इन्हें महंगाई भत्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।खराड़ी प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास होम गार्ड्स के सन्दर्भ में स्वयं सेवक शब्द को हटाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। इससे पहले विधायक श्री हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है। विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों को आवश्यकता होने पर, उनकी मांग अनुसार राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 4 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 के नियम 17 के तहत नामांकित होम गार्ड्स का नियोजन किया जाता है।उन्होंने बताया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 में संशोधन कर होम गार्ड्स सेवा नियम बनाए जाने व होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड, स्थायी एवं अस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत ईपीएफ की सुविधा देय नहीं है।

राज्यपाल ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी राज्यपाल ने कहा यह पूरे देश लिए गौरव की बात

जयपुर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने पेरिस ओलंपिक-2024 में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में शूटिंग में पदक जीतने वाली मनु महिलाओं के लिए ही नहीं सम्पूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्त्रोत है।

राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

अजमेर। जिले के राजस्व मामलों की प्रगति के सम्बन्ध में सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार ने अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त पुलिस जाप्ता एसएचओ, उप पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर से उपलब्ध करवाने की बात कही।

जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने कहा कि राजस्व प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करें। भूमि सम्बन्धी नामांकरण समयबद्ध रूप से नियमानुसार करें। पुराने 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों को विशेष प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें। प्रकरण निस्तारण के समय ऑर्डर सीट स्वयं लिखी जानी चाहिए। भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें। इन्हें 40 दिन की समय सीमा में निस्तारित करें। इस समय सीमा में प्रकरण को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर प्रकरण निस्तारित करें। वर्तमान में अजमेर जिला भू-संपरिवर्तन के प्रकरण निस्तारण में दूसरे स्थान पर है। यह राजस्व से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों की सम्मिलित मेहनत का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि धारा-90ए एवं बिना अनुमति कृषि से गैर कृषि उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करें। पटवारियों द्वारा अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाएं। बैठक में गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। इन प्रकरणों को क्षेत्राधिकार के अनुसार निस्तारित करें। राजस्व वसुली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि महालेखाकार एजी एवं आन्तरिक लेखा जांच दल के आक्षेपों को दूर करने सम्बंधी रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार की जाए। आगामी 12 से 14 अगस्त तक आक्षेपों की पालना के सम्बन्ध में शिविर लगाया जाएगा। इसमें प्रत्येक कार्यालय से कार्मिक उपस्थित होकर पालना सुनिश्चित करेंगे। राजस्व प्रकरणों के स्थगन आदेशों से नोटिफिकेशन से शेष रहे खातों के प्रकरणों की सुनवाई प्राथमिकता से कर स्थगन आदेश के सम्बन्ध में निर्णय प्रदान करें। गर्मी के दौरान गौशालाओं में गायों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के बिलों का तत्काल सत्यापन किया जाए।

पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार ने कहा कि सीमाज्ञान, बंद रास्ते खुलवाने एवं अतिक्रमण के प्रकरणों में पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन को मांगे जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यकता अनुसार पुलिस जाप्ता प्रदान किया जाएगा। कम संख्या में स्थानीय एसएचओ द्वारा उससे अधिक संख्या में उप अधीक्षक द्वारा एवं बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस जाप्ता उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री लोकेश कुमार गौतम, श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं ज्योति ककवानी सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

अजमेर मंडल ने हासिल किया गाड़ी संचालन का 100 प्रतिशत समयपालन

अजमेर। ट्रेनों का समयबद्ध संचालन यात्रियों की सुविधा का ही एक रूप है। गाड़ियों के लेट होने से यात्रियों को असुविधा होती है ऐसे में रेल प्रशासन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि ट्रेनें अनावश्यक लेट न हों।

ट्रेनों के समयबद्ध संचालन हेतु समयपालन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विगत सप्ताह अजमेर मंडल ने 100% समय पालन हासिल किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सुनील कुमार महला के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा समयपालन को सतत रूप से मॉनिटर किया जाता है। अजमेर मंडल के विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय के फलस्वरुप मंडल पर गाड़ियों का समयपालन उच्च स्तर पर रहता है।

समन्वय बैठक आयोजित

अजमेर। विभागों में आपसी समन्वय के लिए सोमवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी ने कहा कि आगामी 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाएगा।

इसकी पूर्व तैयारी विभिन्न स्तरों पर की जाए।

अंगदान की शपथ दिलाने के लिए आमजन को प्रेरित करें।

सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के ब्लॉक निर्माण के लिए पेड़ों को काटने एवं स्थानान्तरित करने के लिए एनओसी प्राप्त की जाए। जेएलएन चिकित्सालय में सेप्टिक टैंक की सफाई तथा पाइप लाईन के कार्य में तेजी लाने से मरीजों को सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित विभाग राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार समय पर कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हैडपम्प खुदाई के कार्यादेश जारी किए गए थे। शेष रहे कार्यों को विवाद रहित कर कार्य पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि अजमेर शहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों की पेयजल टंकियां नगर निगम द्वारा तत्काल साफ करवाई जाए। तरू अजमेर पोर्टल के माध्यम से वृक्षारोपण कर उनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इससे बारिश आने पर पौधारोपण के कार्य को गति मिलेगी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जाए। समस्त चिकित्सालयों में मौसमी बीमारियों से संबंधित आवश्यक दवाईयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध रखें। किसी क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया के पाये जाने पर विभागीय निर्देशानुसार कार्यवाही करें। पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाए।

अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्या की पहचान के लिए चलेगा अभियान

- विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने की अजमेर पुलिस अधीक्षक से चर्चा, अवैध ई-रिक्शा संचालन पर होगी कार्रवाई, समय के बाद शराब बिक्री पर होगी सख्ती

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला पुलिस को शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों व रोहिंग्याओं की धरपकड़ के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अवैध ई-रिक्शा संचालन व समय के बाद शराब बिक्री पर भी सख्ती होगी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर स्थित सर्किट हाऊस में जिला पुलिस अधीक्षक से कानून व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अजमेर के दरगाह सम्पर्क सड़क, दिल्ली गेट व शहर के अन्य हिस्सों में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसी जाए।

कई बार इन अपराधों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की भूमिका सामने आती है। इन सभी के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर धरपकड़ की जाए। इन्हें देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दरगाह सम्पर्क सड़क पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना शीघ्र हो। बजट घोषणा की अनुपालना में हरिभाऊ उपाध्याय नगर में थाने के निर्माण व शुरूआत का काम जल्द करवाया जाए।

देवनानी ने पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र विश्नोई को निर्देश दिए कि अजमेर के आनासागर पुलिस चौकी पर पर्याप्त स्टाफ नियुक्त हो। साथ ही चौकी के नए भवन का निर्माण के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चेन स्नेचिंग व बच्चों को पकड़ने वाला गिरोह पुन: सक्रिय हो रहा है। इनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हो।

गौशाला व कबूतर शाला में किया सेवा कार्य

अजमेर। श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल, अजमेर व श्री राम असहाय सेवा ट्रस्ट की और से सेवाकार्य के तहत श्री सीता गौशाला, पहाड़गंज में गौमाताओं को एक टेम्पू हरा चारा रिजका अर्पित किया गया, संस्था अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, महासचिव प्रवीण अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य कमल किशोर गर्ग तथा अगम प्रसाद मित्तल व सुरेश चंद मंगल ने संस्था की और से अपने हाथों से गौमाताओं को हरा चारा अर्पण किया।

सेवा कार्य की इसी कड़ी में श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल व श्री राम असहाय सेवा ट्रस्ट की

और से ही श्री धर्मार्थ कमेटी कबूतर शाला, सुभाष बाग के पास में कबूतरों के लिये एक कट्टा मक्की, ज्वार दाना अर्पित किया गया। संस्था अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल व श्री राम असहाय सेवा ट्रस्ट के सदस्यों की और से समय समय पर नियमित रूप से ऐसे सेवाकार्य किये जाते रहते हैं तथा इसी क्रम में अगस्त माह में लाडली घर व अपना घर में आवश्यक सेवा कार्य किये जायेंगे।